डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Government of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2025/HQ/Admin/RTI-498

New Delhi: 01.08.2025

श्री संतोष कुमार
पुत्र स्व0 पूरनलाल
निवासी ग्राम दौलतपुर लोहिया,
पोस्ट चांदनपुर, जनपद इटावा,
उत्तर प्रदेश-206126
मोबाइल-9453927835

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन **17.07.2025**, जो इस कार्यालय में दिनांक 24.07.2025 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

श्री दरोगा लाल यादव,
महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
Email ID: dlyadav@dfcc.co.in
मोबाइल-8368028905
DFCCIL कॉर्पोरेट ऑफिस काम्प्लेक्स
सेक्टर-145, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201306

संलग्न: 01 पृष्ठ

(एस. के. पण्डा)
अपर महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)
9717636811

विषय - श्री संतोष कुमार द्वारा आरटीआई अधिनियम-2005 के तहत मांगी गई सूचना।

संदर्भ: RTI. No: 498 dated 24.07.2025.

क्रम संख्या	जानकारी मांगी गई	जवाब
1	मेट्रिक्स की द्वितीय सूची के बिन्दु-4 में अधिग्रहीत की गई भूमि के भू-स्वामी को नौकरी के बदले एक मुश्त भुगतान के लिये रेल मंत्रालय/D.F.C.C.I.L.द्वारा क्या मानदण्ड तय किये गये।	भारत सरकार द्वारा जारी भूमि अधिग्रहण पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन अधिनियम में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार 2013 (RFCTLARR 2013) के क्रम में **रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2009/INFRA/3/1/10 Pt 2 दिनांक 23.05.2015:** यह पत्र DFC परियोजना के लिए नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के अनुसार Entitlement Matrix (हकदारी मैट्रिक्स) के अनुमोदन से संबंधित है। - मेट्रिक्स की द्वितीय सूची के बिन्दु-4 (b) के अनुसार D.F.C.C.I.L के इकाई से संबंधित जिले द्वारा दिया जा रहा हैं।
2	नौकरी के बदले एक मुश्त धनराशि अदा किये जाने के वास्ते उच्च स्तर पर मानदण्ड तय करने के लिये आयोजित की गई बैठक में लिखे गये मिनट्स/नोट्स की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।	भारत सरकार (रेल मंत्रालय) द्वारा जारी भूमि अधिग्रहण पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन अधिनियम में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार 2013 (RFCTLARR 2013) के क्रम में **रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2009/INFRA/3/1/10 Pt 2 दिनांक 23.05.2015 के द्वारा DFC Project के** Entitlement Matrix प्रदान की गई हैं अतः इस से संबंधित मिनट्स/नोट्स की प्रति DFCCIL कार्यालय मे उपलब्ध नहीं है ।
3	नौकरी के बदले एक मुश्त भुगतान के लिये ग्रामवार अथवा तहसीलवार मापदण्ड तय किये गये अथवा जिलावार तय किये गये। स्पष्ट सूचना उपलब्ध करायें।	आपने सभी कॉरिडोर से संबंधित जानकारी मांगी है, जिसमें 11 इकाइयाँ शामिल हैं जो अलग-अलग भौगोलिक स्थानों पर स्थित हैं। चूँकि यह जानकारी केंद्रीकृत तरीके से उपलब्ध नहीं है। अतः आप संबंधित जिले से सूचना प्राप्त करे , जिस जिले द्वारा एक मुश्त भुगतान की जा रही हैं ।

Amrish Kumar
AM/SEMU/APIO
29.07.2025

GM/LA&SEMU
29.7.25

AGM/Admn (PIO)